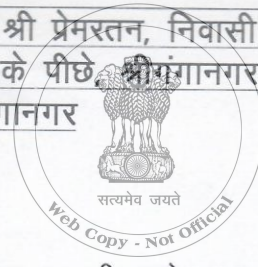


अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2017 अनवानी श्री प्रेमरतन, निवासी म0न0
38, नागपाल कॉलोनी, गली नम्बर 1, सिटी मॉल के पीछे, श्रीगंगानगर बनाम
लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर



31-07-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26-04-2017 के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 2एच का उल्लेख करते हुए सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है जबकि चाही गई सूचना स्पष्ट व पारदर्शी है जो अपीलार्थी को उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरुद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रेमरतन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण इलाको में कैरोसीन व गेहूं का कुल कितना आवंटन हुआ व किस किस डिपो पर कितना आवंटन किया गया।
2. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक सभी श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण डिपो होल्डर की पॉस मशीन से बिना आधार कार्ड के कितना कैरोसीन व गेहूं वितरण किया गया।
3. सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण में पॉस मशीन के अलावा रजिस्टर में किस किस डिपो पर कितना कैरोसीन व गेहूं व चीनी वितरण किया गया।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3580 दिनांक 21.06.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2च व 7(9) के तहत देय नहीं होने से उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3046 दिनांक 17.05.17 के द्वारा समय अवधि में आवेदक को सूचित कर दिया गया था। अतः अपील निरस्त की जावे।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 3 बिन्दुओं की सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 3046 दिनांक 17.05.17 के द्वारा उसे निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:-

सा.न.
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिए। चूंकि खोजकर खोजे गए तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प0 22 (16) प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नहीं है। रिट पेटिशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना कि परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 17.05.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

678-23
7-9-17